5 वां कटऑफ जारी किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शुक्रवार को। इसके तहत 23 जुलाई तक दाखिले होंगे। छात्र-छात्राओं के लिए हिंदू, गार्गी, कमला नेहरू कॉलेज में अभी है दाखिले का अवसर।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 20 जुलाई 2019

अत्याधुनिक हथियार देखना चाहते हैं तो प्रगति मैदान आएं

- दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो शुरू, 25 देश हैं भागीदार
- 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन हुए हैं शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

प्रगति मैदान में शुक्रवार को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आगाज हुआ है। इसमें सिंगापुर, इजराइल, कोरिया, ताइवान, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, मलेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व पोलैंड सहित 25 देशों ने भागीदारी की है। एक्सपो में इन देशों द्वारा नवीनतम तकनीक से बनाए गए हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्सपो का उद्देश्य पुलिस आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्नत हथियार, सुरक्षा व बचाव की आधुनिक तकनीकों के साथ ही साइबर सुरक्षा से जुड़ी नवीनतम तकनीक को जानने व देश में उनके इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशना है।

देश की पुलिस, नागरिक सुरक्षा और होमलैंड सिक्योरिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस एक्सपो को आयोजन नेक्सजेन एक्जिबिशन द्वारा किया गया है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य रवींद्र किशोर सिन्हा ने एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे दुश्मनों की पहचान करना आसान है, जिन्हें सीमाओं पर देखते हैं, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की पहचान करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में पुलिस का आधुनिकीकरण की उपेक्षा करने से गंभीर खतरा पैदा होगा।

प्रगति मैदान में आयोजित इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में हथियारों को देखते लोग। जागरण

एक्सपो में सौ से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हुए। इन संगठनों ने नागरिक सुरक्षा से जुड़े हथियारों के साथ मुश्किल हालात में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों का प्रदर्शन किया है। आयोजन के बारे में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो के आयोजक वीके बंसल ने कहा कि एक उन्नत, कुशल और प्रभावी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की जरूरत है, जो संभावित रूप से 21 वीं सदी के तेजी से बदलते खतरे से निपट सकती है।

कनाडा की कंपनी ने पेश किया सबसे हल्का बम निरोधक सूट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बम को निष्क्रिय करते समय या उसे ढूंढ़ते समय सुरक्षा के लिए बम निरोधक सूट पहना जाता है। भारी भरकम सूट के कारण होने वाली परेशानी को कम करने के लिए कनाडा की एक कंपनी ने सबसे हल्का बम निरोधक सूट तैयार किया है। इसे प्रगति मैदान में आयोजित इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में प्रदर्शित किया गया।

सामान्य तौर पर बम निरोधक सूट का वजन करीब 35 किलोग्राम या इससे भी ज्यादा होता है। कंपनी द्वारा तैयार किए गए ईओडी-10 सूट का वजन 30 किलोग्राम है। यह सूट धमाके, आग के गुबार और गर्मी से बचाने में पूरी तरह से सक्षम है। इस सूट के साथ डिजाइन किया गया हेलमेट भी मौजूदा हेलमेट की तुलना में अधिक सुरक्षित बताया जा रहा है। कंपनी की दावा है कि सूट को पहनकर एक मीटर के दायरे में हुए आधा किलो आरडीएक्स के धमाके को सहा जा सकता है। इसके अलावा सूट में इंटीग्रेटेड वॉइस कमांड भी लगाया गया है, जिससे बम को ढूंढने या उसे निष्क्रिय करते समय सूचनाओं ठीक तरीके से आदान-प्रदान किया जा सके।

एक्सपो में प्रदर्शित बम निरोधक सूट। जागरण

हीट के कारण होने वाली उलझन और परेशानी दूर को करने के लिए इस सूट में वेंटीलेशन की व्यवस्था करने के साथ कूलिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया है। इस सूट का कूलिंग सिस्टम रीढ़ ही हड्डी के पास के हिस्से को ठंडा रखता है, जिससे सूट पहने हुए व्यक्ति को काम करने में दिक्कत नहीं होती है।

सबसे कम वजनी बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच लांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने देश की सबसे कम वजनी बुलेटप्रूफ जैकेट भाभा कवच लांच की। भाभा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट हैदराबाद की कंपनी ने बनाई है। यह अत्याधुनिक जैकेट एके-47, मिनी इंसास और एसएलआर से चली हुई गोलियों और 7.62 एमएम हार्ड स्टील कोर गोलियों का सामना कर सकती है। यह 360 डिग्री में सुरक्षा प्रदान करती है। यह जैकेट एनआइजे ट्रिपल आइ प्लस सुरक्षा स्तर की है।

जैकेट का वजन 9 किलो 200 ग्राम है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। भाभा कवच के तौर पर अब भारतीय रक्षा बलों के लिए हल्की और बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध हो पाएगी। यह अर्धसैनिक बलों और नक्सली क्षेत्रों में सक्रिय राज्य पुलिस बलों के लिए बेहद अहम साबित होगी। जैकेट को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने नैनो तकनीक से विकसित किया है। जैकेट को एक्सपो में प्रदर्शित किए जाने के बाद सशस्त्र बलों की तरफ से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। साथ ही पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात सहित कई अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने भी जैकेट में दिलचस्पी दिखाई और सवाल पूछे। कश्मीर में आतंकी स्टील बुलेट से हमला कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को यह जैकेट उपलब्ध कराई जाए। आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों के मुताबिक जैकेट को गृह मंत्रालय से अप्रूवल मिल चुका है।

भाभा कवच नाम से तैयार की गई बुलेट प्रूफ जैकेट। जागरण

न्यूज गैलरी

दिल्ली पुलिस के कई बड़े अफसरों के हुए तबादले

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरेटरी) के 20 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इनमें कुछ दिल्ली से बाहर भी भेजे गए हैं। क्राइम ब्रांच के संयुक्त आयुक्त रहे रविंद्र यादव को दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है। वहीं पश्चिमी रेंज के संयुक्त आयुक्त मधुप तिवारी को अंडमान निकोबार भेजा गया है। एडिशनल कमिश्नर आरए संजीव को मिजोरम भेजा गया है। दीपक पुरोहित, पीयूष फुलजले और भरत रेड्डी को अरुणाचल प्रदेश, शोभित सक्सेना को गोवा और अनंत मित्तल को अंडमान निकोबार भेजा गया है। मिजोरम से एमएन तिवारी को दिल्ली बुलाया गया है। एडिशनल कमिश्नर बनने के बाद इनकी पहली तैनाती होगी। इनके अलावा सुनील गर्ग को अरुणाचल प्रदेश से, दीपक यादव, शालिनी सिंह और विमल आनंद गुप्ता को अंडमान निकोबार से, ओपी मिश्रा को चंडीगढ़ से, रोहित मीणा और जितेंद्र कुमार मीणा को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली में तैनात किया गया है। (जासं)

एम्स ट्रॉमा सेंटर में दोबारा शुरू हुए दो ओटी, मरीजों को राहत

नई दिल्ली : एम्स ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से जले दो ऑपरेशन थियेटर (ओटी) दोबारा शुरू हो गए हैं। अब दोनों ओटी में मरीजों की सर्जरी शुरू हो गई है। इससे एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिली है। (जासं)

150 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी, पांच गिरफ्तार

सफलता ▸ पुलिस का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी खेप है, मार्च में पकड़ी गई थी 83 किलो हेरोइन

गिरफ्तार तस्करों में दो अफगानी नागरिक भी हैं शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने हेरोइन की तस्करी के एक बड़े तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें दो अफगानी नागरिक सहित पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 150 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि दिल्ली में पकड़ी गई हेरोइन की यह अब तक की सबसे बड़ी खेप है। इससे पहले मार्च में स्पेशल सेल ने 83 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी थी। हेरोइन की तस्करी दिल्ली-एनसीआर और पंजाब सहित श्रीलंका में की जाती थी।

स्पेशल सेल के डीसीपी मनीषी चंद्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस लगातार तस्करों पर नजर रख रही है। पुलिस को सूचना मिली कि दक्षिण पूर्व जिले में लगातार लग्जरी कार की संदिग्ध आवाजाही हो रही है। कारों में देर रात अथवा तड़के भारतीय के अलावा अफगानी और अफ्रीकी मूल के लोग आते-जाते दिख रहे थे। इस पर पुलिस ने नजर रखनी शुरू की। इसमें पता चला कि इलाके में एक ड्रग्स तस्कर गिरोह सक्रिय है, जो अफगानिस्तान से हेरोइन लाकर इसकी तस्करी देश सहित श्रीलंका में कर रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर सुनील, रविंद्र जोशी और विनोद बाडोला की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस से तस्करों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इसी बीच उनकी गतिविधियों का पता चलने पर पुलिस ने 17 जुलाई की आधी रात बाद आश्रम फ्लाईओवर के पास से दो संदिग्ध कारों को रुकवाया और उसकी तलाशी ली। उनमें 30-30 किलो कुल 60 किलो हेरोइन बरामद हुई। तस्कर धीरज और रईस खान को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कार की पीछे की सीट और डिक्की के बीच बनाए गए गुप्त स्थान पर हेरोइन के पैकेट छिपा रखे थे। तस्करों से पूछताछ में पता चला कि जाकिर नगर इलाके में हेरोइन की प्रोसेसिंग यूनिट है। वहीं से तस्करी की जा रही है। पुलिस की टीम ने जाकिर नगर स्थित मकान में छापा मारकर दो अफगानी तस्करों सहित तीन लोगों को धर दबोचा। हेरोइन की प्रोसेसिंग यूनिट से 60 किलो, जबकि अन्य तस्कर की कार में छिपाकर रखी गई 30 किलो हेरोइन बरामद की गई। उन तस्करों की पहचान शिनवारी रेहमत, अख्तर मुहम्मद शिनवारी और वकील अहमद के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि शिनवारी रेहमत और अख्तर मुहम्मद शिनवारी अफगानिस्तान के जलालाबाद के हैं और दोनों कैमिकल एक्सपर्ट हैं। वे अफगनिस्तान से आए कच्चे माल को रसायनों से परिस्कृत कर उससे उम्दा किस्म की हेरोइन बनाते थे। बाद में उसकी आपूर्ति भारत के विभिन्न राज्यों सहित विदेश में की जाती थी। पुलिस अब मास्टर माइंड के अलावा गिरोह के अन्य तस्करों की गिरफ्तारी में जुटी है।

अफगानिस्तान से विशेष तरीके से मसाले के बोरे में भारत लाते थे हेरोइन : पुलिस अधिकारी ने बताया कि तस्कर अफगानिस्तान से भारत हेरोइन लाने के लिए विशेष प्रकार की युक्ति अपनाते थे। अफगानिस्तान से भारी मात्रा में मसाले भारत में आयात होते हैं। तस्कर मसाले के जूट के बोरों को हेरोइन मिले रसायन में भिगो कर उसे सुखा लेते थे। बाद में उन बोरे में मसाले भर भारत भेज दिया जाता था। तस्कर उन बोरों पर विशेष नजर रखते थे। भारत में मसाले पहुंचने के बाद हेरोइन सूखे बोरों को एकत्र कर लिया जाता था। उसके बाद जाकिर नगर स्थित प्रोसेसिंग यूनिट में बोरों को अलग-अलग रसायन में डुबोकर हेरोइन को बोरे से अलग कर दिया जाता था। एक बोरी से निकले तत्व से करीब एक किलो हेरोइन बनती थी। वहीं, परिस्कृत करने के बाद हेरोइन का पैकेट बना उसकी तस्करी की जाती थी।

दिल्ली में हेरोइन बरामदगी के बड़े मामले

15 मार्च 2019 : स्पेशल सेल ने 83 किलोग्राम हेरोइन के साथ 12 तस्करों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान और म्यांमार से तस्करी कर लाई गई थी हेरोइन।

3 मार्च 2019 : स्पेशल सेल ने अफगानिस्तान मूल के चार ड्रग तस्करों को दबोचा, 920 ग्राम हेरोइन के 122 कैप्सूल बरामद

21 जनवरी 2019 : स्पेशल सेल ने ड्रग तस्करों के दो गिरोह के छह बदमाशों को पकड़ा। इनके पास से 20 किलो हेरोइन बरामद

22 दिसंबर 2018 : स्पेशल सेल ने अंतरराष्ट्रीय हेरोइन तस्कर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 30 किलो हेरोइन बरामद

17 अक्टूबर-2018 : स्पेशल सेल ने 25 किलो हेरोइन की तस्करी का किया पर्दाफाश, दो तस्कर गिरफ्तार

10 अप्रैल 2018 : पुलिस ने 29 किलोग्राम हेरोइन के साथ अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह के तीन तस्करों को दबोचा

स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार हेरोइन तस्कर (बाएं)। तस्करों से बरामद हेरोइन (बीच में)। हेरोइन छिपाने के लिए इस तरह कार में बनाया गया था गुप्त स्थान (दाएं)। सौजन्य : दिल्ल पुलिस

'केजरीवाल ने केंद्र के आदेश पर भी अनधिकृत कॉलोनियों को नहीं किया नियमित'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर भाजपा ने लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला जारी रखा। उसका कहना है कि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद केजरीवाल ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही इन कॉलोनियों के विकास के लिए आवंटित फंड का भी दिल्ली सरकार उपयोग नहीं कर पाई।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने एक जनवरी, 2015 तक 50 फीसद से ज्यादा हो चुके निर्माण को नियमित करने के लिए कहा था। दिल्ली सरकार ने इस आदेश को छिपाने के साथ ही यह भ्रम फैलाया कि केंद्र में दोबारा मोदी सरकार आने पर अनधिकृत कॉलोनियां गिरा दी जाएंगी। केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर सितंबर, 2016 में दो बार दिल्ली सरकार को बुलाया भी था, लेकिन इनका रवैया नकारात्मक रहा। अनधिकृत कॉलोनियों की सीमा तय करने के लिए आप सरकार ने 2017 में दो साल का समय मांगा था, लेकिन कोई काम करने के बजाय अब फिर से दो साल का समय मांग लिया है। मजबूरन केंद्र सरकार को अपने स्तर पर सर्वे कराने का फैसला लेना पड़ा। अब केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया तो केजरीवाल इसका श्रेय लेने के लिए आगे आ गए हैं।

यातायात पुलिस का ई-चालान और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने शुक्रवार को ई-चालान और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। इस सिस्टम के जरिये वाहन चालकों का चालान पंजीकृत वाहन के पंजीकरण नंबर के जरिये पंजीकृत नंबर पर एसएमएस के जरिये भी पहुंचेगा और पंजीकृत वाहन के पते पर भी पहुंचेगा। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के चालू होने के बाद लोग अब किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ-साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक नेट बैंकिंग से भी चालान का भुगतान कर सकेंगे। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नई तकनीक से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों को चालान का भुगतान करने में सुविधा होगी। इस सिस्टम की शुरुआत में एक हजार मशीनें यातायात पुलिस विभाग को दी गई हैं, जिससे मौके पर चालान किए जाने के साथ भुगतान भी क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड के जरिये किया जा सकेगा। यह परियोजना पूरी तरह से गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।

ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा एनआइसी के पास उपलब्ध : एनआइसी यानी राष्ट्रीय सूचना केंद्र की ज्यादातर सेवाएं दिल्ली पुलिस को मुफ्त दी जाती हैं। एनआइसी सॉफ्टवेयर सपोर्ट, डेवलपमेंट के लिए मैनपावर और सर्वर, डिजास्टर साइट्स, एनसीआरबी, आइआरडीए और देश की विभिन्न राज्य परिवहन प्राधिकरण के डेटाबेस को एकीकृत करके तकनीकी सहयोग कर रहा है।

एनआइसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन मालिकों का भी पूरा डेटाबेस उपलब्ध है। वाहन और सारथी एप के जरिये वाहन चालक के लाइसेंस के जरिये और वाहन के नंबर के जरिये दोनों की पूरी जानकारी जुटाई जा सकती है।

चालान के समय पता लगेगा वाहन चोरी का तो नहीं : जिस समय दिल्ली पुलिस किसी भी वाहन का चालान करेगी तो वाहन के नंबर के आधार पर उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ई-चालान सिस्टम एनसीआरबी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा वाहन का नंबर दर्ज करते ही यह पता लग जाएगा कि वाहन चोरी का तो नहीं है और पहले कितनी बार वाहन का चालान हो चुका है।

अन्य राज्यों की पुलिस के पास भी पहुंचेगा चालान का डाटा : जिस भी वाहन का चालान कटेगा, उस वाहन की संख्या के आधार पर संबंधित राज्य के आरटीओ के पास भी वाहन का चालान होने की जानकारी मिल जाएगी। इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सारथी एप के जरिये एनसीआरबी से सभी वाहन चालकों के लाइसेंस का डेटा भी लिया गया है। जिससे वाहन चालक के लाइसेंस का नंबर डालते ही सिस्टम उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा देगा। इससे यह भी पता लग जाएगा कि लाइसेंस फर्जी तो नहीं है।

वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले में याचिका पर सुनवाई टली

जासं, नई दिल्ली : वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस अदालत में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई नौ अगस्त के लिए टाल दी गई। दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग को लेकर पीड़िता के परिजनों ने अदालत में याचिका दायर की थी।

16 दिसंबर 2012 की रात में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। कुछ दिनों बाद पीड़िता ने इलाज के दौरान सिंगापुर में दम तोड़ दिया था। इस मामले के एक दोषी ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य नाबालिग को कोर्ट ने तीन साल के लिए बाल सुधार गृह में भेजने की सजा सुनाई थी। वहीं अन्य चार अन्य दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद दोषियों ने फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी। हालांकि दया याचिका को खारिज कर फांसी की सजा बरकरार रखने का आदेश दिया गया था।

कानून वही चुनें जिससे जनता को लाभ हो : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के 50 सफल अभ्यर्थियों के एक समूह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे अधिकारी लिखे हुए शब्दों के गुलाम बन जाते हैं। कानून लोगों की सेवा के लिए बनाए गए हैं न कि उनकी सेवा से बचने का रास्ता बनाने के लिए। अगर किसी कानून की एक से अधिक व्याख्या है तो वह चुनें जिससे लोगों का फायदा हो। केजरीवाल ने कहा कि आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं भी 1992 बैच का एक आइआरएस ऑफिसर रह चुका हूं। मैंने अपनी सर्विस 1995 में शुरू की थी। अब मैं एक अलग प्रोफेशन में हूं। आप सब अपने आदर्शवाद का उपयोग जनता के भले के लिए कीजिएगा। अपनी सेवा के दौरान आम जनता के लिए उपलब्ध रहना ताकि लोग आप सबको हमेशा याद रखें। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से अपने अनुभव भी साझा किए।

नौकरशाहों के पास असाधारण होती हैं शक्तियां : मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सिविल सेवा ज्वाइन करने के पीछे क्या प्रेरणा है? ये वे सवाल हैं जो आप सबसे इंटरव्यू में पहले पूछे गए होंगे। तकरीबन 100 फीसद अभ्यर्थियों का जवाब होता है कि वह राष्ट्र की सेवा के लिए सिविल सेवा में आना चाहते हैं। अगर ये वास्तव में सच है तो आजादी के 70 साल बाद अब तक देश को महान ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरशाहों के पास असाधारण शक्तियां होती हैं और अगर कोई नौकरशाह देश के लिए कुछ करना चाहता है तो ऐसा करने के लिए उसके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं।

देश हमारी शिक्षा के लिए बहुत योगदान करता है : केजरीवाल ने कहा कि मैंने आइआइटी खड़गपुर से पढ़ाई की जहां उस समय मेरी फीस 32 रुपये प्रति महीने हुआ करती थी। जाहिर सी बात है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च 32 रुपये महीने नहीं हो सकता। आप सोच सकते हैं कि मेरी आइआइटी की पढ़ाई में कितनी अधिक सब्सिडी शामिल थी। इसी तरह डॉक्टर और अन्य विषयों की पढ़ाई में इस देश के लोगों की तरफ से सब्सिडी दी जाती है।

केजरीवाल ने कहा कि हम में से 90 फीसद लोग आदर्शवाद के साथ ये सेवा ज्वाइन करते हैं, लेकिन वक्त के साथ हम सभी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यही गलत है। जीवन में रोमांच होना चाहिए और ये सेवा आपको बहुत सारा रोमांच देती है।

यूपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सौजन्य : दिल्ली सरकार

तैयारी

राजधानी में होटल, मोटल और फार्महाउसों में होने वाले शादी-समारोहों में अब खाने की बर्बादी नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सोशल फंक्शन पॉलिसी तैयार की है।

बरातियों की संख्या तय करने वाली नीति मात्र दो कदम दूर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राजधानी में होटल, मोटल और फार्महाउसों में होने वाले शादी-समारोहों में अब खाने की बर्बादी नहीं होगी। समारोह स्थलों के बाहर जाम भी नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सोशल फंक्शन पॉलिसी तैयार की है। दिल्ली सरकार ने पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर डीडीए के पास अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया है। डीडीए इसके लिए मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करेगा। इसके बाद अधिसूचना जारी कर देगा। इस पॉलिसी के अनुसार, अब शादी समारोह के लिए स्थानीय निकायों को सात दिन पहले बताना होगा कि बराती कितने होंगे। यह भी निर्धारित करना होगा कि घुड़चढ़ी सड़क पर नहीं होगी। जितनी कारों की व्यवस्था होगी उससे चार गुना अतिथि ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। बैंडबाजे का समय 10 बजे तक ही निर्धारित होगा।

नीति को लेकर जनता व फार्महाउस मालिकों की ओर से कुछ सुझाव दिए गए हैं, इन पर फैसला लिया जाना है। इसके बाद नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने होटल, मोटल और फार्महाउसों में खाना और पानी की बर्बादी रोकने के लिए नीति तैयार कर दी है। इस नीति में क्या है खास आइए डालते हैं एक नजर।

सुरक्षा राशि के रूप में पांच लाख की राशि जमा करानी होगी : इस नीति के लिए मुख्यसचिव विजय देव ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी से चर्चा के बाद नीति का मसौदा तैयार किया गया है। आयोजक को किसी भी आयोजन के लिए कार्यक्रम स्थल के संचालक के पास पांच लाख की सुरक्षा राशि जमा करानी होगी।

कार्यक्रम में कितने मेहमान आएंगे। कार्यक्रम कितने समय से शुरू होगा, कब समाप्त होगा। खाना बचता है तो जरूरतमंदों के लिए वे किस संस्था या एनजीओ के पास पहुंचाएंगे, इसकी जानकारी देनी होगी। एनजीओ या संस्था का नाम, पता व टेलीफोन नंबर भी देना होगा। शिकायत के लिए एक कॉमन पोर्टल बनेगा जिसमें सभी एजेंसियां शामिल होंगी। कार्यक्रम स्थल का मालिक, ऑपरेटर या जिसे कार्यक्रम आयोजित करना है, वह अनुमति लेने के लिए इस पोर्टल पर आवेदन करेगा।

ये होंगी शर्तें

- अधिकृत होटल, मोटल या फार्महाउस में ही कार्यक्रम की अनुमति होगी
- एक साल में 120 आयोजन ही कर सकेंगे होटल, मोटल व फार्महाउस मालिक
- कार की पार्किंग की व्यवस्था से चार गुणा ज्यादा हो सकेगी अतिथियों की संख्या
- घुड़चढ़ी सड़क पर नहीं होगी और दस बजे के बाद बैंडबाजे की अनुमति नहीं होगी
- आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार और निकास द्वार की सीसीटीवी रिकार्डिंग 30 दिन तक रखना अनिवार्य होगा
- दिल्ली अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट प्रबंधन भी नियमों के अनुसार करना होगा
- बिजली पानी की व्यवस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुरूप करनी होगी
- वही कैटरर खाना बनाने और परोसने का काम कर सकेगा जिसने स्वास्थ्य विभाग से सुरक्षित खाना परोसने का लाइसेंस लिया होगा

एनएसजी कैंपस में कमांडो ने नाबालिग से की छेड़छाड़

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के मानेसर ट्रेनिंग सेंटर में तैनात एक कमांडो पर 11 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। लड़की की मां की शिकायत पर एनएसजी के अधिकारियों ने पहले आंतरिक जांच की। इसमें शिकायत सही पाई गई तो एनएसजी के ग्रुप कमांडर एनके शर्मा ने महिला थाना पुलिस मानेसर में आरोपित कमांडो के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी।

पुलिस के मुताबिक लड़की की मां एनएसजी कैंपस में ही मिले आवास में रहती है। 15 जुलाई को दोपहर बाद मां ने लड़की को कैंटीन से दही लाने के लिए भेजा था। वहां से लौटते वक्त लड़की को कमांडो प्रवीन मिल गया। आरोप हैं कि उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की। घर लौटने पर लड़की ने मां को उसकी करतूत बताई। लड़की की मां ने ग्रुप कमांडर एनके शर्मा को लिखित में शिकायत दी। शिकायत मिलते ही मामले की आंतरिक जांच कराई गई। इसमें मामले की पुष्टि होने के बाद एनके शर्मा ने महिला थाना पुलिस में आरोपी कमांडो के खिलाफ शिकायत दी।

कांग्रेस में घमासान, चिंता में भाजपा के रणनीतिकार

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के बाद से दिल्ली कांग्रेस में शुरू हुए घमासान ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी के नेता कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई पर नजर रख रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि यदि कांग्रेसियों के बीच लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो इसका खामियाजा कहीं उन्हें विधानसभा चुनाव में न भुगतना पड़े। दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) के उदय के बाद दिल्ली की चुनावी सियासत में त्रिकोणीय मुकाबला होने लगा है। वर्ष 2013 से लेकर अबतक हुए सभी चुनावों में आप, भाजपा व कांग्रेस के बीच मुकाबले हुए हैं। इन चुनावों में कांग्रेस की कमजोरी का सीधा लाभ आप को मिला है और यही समीकरण भाजपा रणनीतिकारों के लिए चिंता का सबब है।

दिल्ली में परंपरागत रूप से भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था, लेकिन अब यहां का सियासी समीकरण बिल्कुल बदल गया है। आप जहां दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने में सफल रही है तो कांग्रेस हाशिये पर चली गई है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दिल्ली की सातों सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन उसके कुछ माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसे मात्र तीन सीटें नसीब हुई थी। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल सका था। दूसरी ओर आप 70 में 67 सीटें जीतकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गई। हालांकि, बाद में हुए नगर निगम चुनाव में भाजपा शानदार जीत हासिल करने के साथ ही इस लोकसभा चुनाव में भी बड़े अंतर से दोबारा सातों सीटें जीतने में सफल रही है। अब उसकी नजर दिल्ली की सत्ता पर टिकी हुई है। भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इस बीच कांग्रेस में शुरू हुई लड़ाई से पार्टी नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है। इसके कारण भी हैं। यह माना जाता है कि कांग्रेस के परंपरागत वोटरों को अपने साथ करके आप ने पिछले विस चुनाव में जीत हासिल की थी।